यूको बैंक UCO BANK

(भारत सरकार का उपक्रम)
प्रधान कार्यालय, वित्त विभाग, तीसरा तल
2, इंडिया एक्सचेंज प्लेस, कोलकाता-700 001

प्रस्ताव के लिये अनुरोध

यूको बैंक अपनी वेबसाइट www.ucobank.com पर मौजूद प्रस्ताव अनुरोध के दस्तावेजो में दिए गये विवरण के अनुसार उपयुक्त बोलीदाताओ को बैंक के विभिन्न पुंजीयो का सुरक्षा बीमा करने हेतु सीलबंद लिफाफे मे प्रस्ताव आमंत्रित करता है।
बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख एवं समय 15.06.2022 को पूर्वाह्न 11 बजे तक है।

सहायक महाप्रबंधक (वित्त)

सम्मान आपके विश्वास का

बैंक ऑफ़ इंडिया
रिश्तों की जमापूँजी

प्रधान कार्यालय: स्टार हाउस, प्लाट: सी 5, जी ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051
फोन: 022 6668 4448 / 6668 4441
ई-मेल: headoffice.publicity@bankofindia.co.in

निविदा सूचना

बैंक ऑफ इंडिया वर्ष 2022-23 के लिए चांदी के फलक और चांदी के पदक खरीदने के लिए प्रतिष्ठित चांदी निर्माताओं से निविदाएं आमंत्रित करता है. निविदा दस्तावेज बैंक की वेबसाइट पर निविदा अनुभाग में रखा जायेगा. निविदा की प्रस्तुति 20.05.2022 से आरंभ होगी और निविदा प्रस्तुति की अंतिम तारीख 09.06.2022 होगी. शुद्धिपत्र, यदि कोई होगा तो, बैंक की वेबसाइट पर ही प्रकाशित/रखा जायेगा. कृपया निविदा दस्तावेज डाउनलोड करने के लिए हमारी वेबसाइट **www.bankofindia.co.in** देखें.

महाप्रबंधक
दिनांक: 20/05/2022 प्रचार एवं जनसंपर्क विभाग, प्रधान कार्यालय

MIDHANI
मिश्र धातु निगम लिमिटेड
कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन): L14292TG1973GOI001660
पंजीकृत कार्यालयः पीओ - कंचनबाग, हैदराबाद - 500058, तेलंगाना
दूरभाष नंबरः 040-2418 4515 फैक्स नंबरः 040-2434 0214
ई-मेल पताः company.secretary@midhani-india.in वेबसाइटः www.midhani-india.in

पोस्टल बैलट/ई-वोटिंग से सम्बन्धित सूचना

कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय द्वारा जारी लागू दिशानिर्देशों/परिपत्रों ('एमसीए परिपत्र') के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 और 110 और उसके तहत बनाए गए नियमों और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के अनुसार, सदस्य कृपया ध्यान दें कि मिश्र धातु निगम लिमिटेड (मिधानी) पोस्टल बैलट/इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों ('पोस्टल बैलेट') प्रक्रिया द्वारा मतदान के माध्यम से पोस्टल बैलेट सूचना ('सूचना') जो सदस्यों को उचित समय पर भेजी जाएगी, में निर्धारित व्यवसाय(यों) का लेन-देन करने के लिए सदस्यों की सहमति प्राप्त करना चाहता है।
एमसीए परिपत्रों के अनुसार, ई-वोटिंग के लिए प्रक्रिया एवं निर्देशों के साथ सूचना की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी/संस्करण केवल उन्हीं सदस्यों को भेजा जाएगा जिनकी ईमेल आईडी कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों (डीपी) के साथ पंजीकृत है।
जिन सदस्यों ने अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं किया है, उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित शेयरों के संबंध में अपने डिपॉजिटरी सहभागियों के साथ और भौतिक रूप में धारित शेयरों के संबंध में कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) अर्थात अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड (अलंकित) को फोलियो नंबर और पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति के विवरण के साथ अलंकित असाइनमेंट लिमिटेड, अलंकित हाउस, 4ई/2, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली -110 055 के पास लिखित रूप में या rta@alankit.com पर ई-मेल भेजकर पंजीकृत करें। सदस्य कंपनी को company.secretary@midhani-india.in पर ई-मेल भी भेज सकते हैं।
सदस्यों को अपना ई-मेल पता अपडेट करके वार्षिक रिपोर्ट, सामान्य बैठक की सूचना और अन्य प्रासंगिक संचार इलेक्ट्रॉनिक साधन द्वारा मिधानी से प्राप्त होंगे। सदस्यों के हित में यह सलाह दी जाती है कि वे अपना ई-मेल पता यथाशीघ्र पंजीकृत/अद्यतन करें।
कंपनी सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान करेगी और ई-वोटिंग प्रक्रिया से संबंधित तरीके, निर्देश और अन्य जानकारी (सदस्य जो भौतिक रूप में शेयर धारण करते हैं या जिन्होंने अपना ई-मेल पंजीकरण नहीं किया है, ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने की रीति सहित), सूचना का हिस्सा होगा।
उचित समय पर, सूचना जारी होने पर, कंपनी की वेबसाइट www.midhani-india.in और स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात बीएसई और एनएसई की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com तथा www.nseindia.com पर उपलब्ध होगा।

मिश्र धातु निगम लिमिटेड के लिए
ह./-
स्थानः हैदराबाद पॉल एंटोनी
दिनांकः 20 मई,2022 कंपनी सचिव

SBI
भारतीय स्टेट बैंक
(भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, १९५५ के अंतर्गत गठित)
शेयर एवं बॉण्ड विभाग, कॉर्पोरेट सेन्टर, 14वीं मंजिल, स्टेट बैंक भवन, मैडम कामा रोड, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400021
वेबसाइट: https://bank.sbi ई-मेल: investor.complaints@sbi.co.in
फोन नं: 022-22741474, 22740847, 22742403, 22740841, 22740846, 22740843

कृपया ध्यान दें: शेयरधारक
लाभांश की घोषणा, लाभांश पर कर की कटौती और बुक क्लोजर की सूचना

प्रिय शेयरधारकों,
हम अत्यंत हर्ष के साथ अपने प्रतिष्ठित शेयरधारकों को सूचित करते हैं कि आपके बैंक के केंद्रीय बोर्ड ने 13 मई 2022 को आयोजित बैठक में 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के लिए रु. 7.10/- प्रति इक्विटी शेयर (अंकित मूल्य रु. 1/-) के लाभांश की घोषणा की है. डिविडेंड के भुगतान के लिए रिकॉर्ड दिनांक 26 जून 2022 होगी. डिविडेंड का भुगतान 10 जून 2022 को किया जाएगा.
2. एतद्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय स्टेट बैंक का शेयरधारकों का रजिस्टर वि.व. 2021-22 के लिए लाभांश के भुगतान हेतू शेयर्स का ट्रांसफर करने के लिए 27.05.2022 (शुक्रवार) से 31.05.2022 (मंगलवार) तक बंद रखा जाएगा.
3. वित्त विधेयक 2020 द्वारा संशोधित आयकर क़ानून, 1961 (कानून) के अनुसार बैंक द्वारा 01 अप्रैल, 2020 के बाद किए या वितरित किए जाने वाले लाभांश नीचे दिए अनुसार शेयरधारकों के हाथों में कर योग्य होंगे:
 I. निवासी शेयरधारकों के लिए, आयकर क़ानून, 1961 की धारा 194 के अंतर्गत वि.व. 2022-23 के दौरान बैंक द्वारा घोषित और अदा किए गए लाभांश की राशि पर 10% की दर से कर स्त्रोत पर कटौती योग्य होगा, बशर्ते शेयरधारक द्वारा पैन प्रदान किया गया हो. यदि पैन उपलब्ध नहीं है, तो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 206AA के अनुसार 20% की दर से टीडीएस काटा जाएगा.
 II. वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान निवासी व्यक्ति द्वारा प्राप्त कुल लाभांश रु. 5000/- से अधिक नहीं होता है तो उसे देय लाभांश पर टीडीएस नहीं काटा जाएगा. कृपया ध्यान दें कि इसमें भावी लाभांश, यदि हो, शामिल है, जिसकी घोषणा आपके बैंक के केंद्रीय बोर्ड द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान की जा सकती है.
 III. आयकर कानून, 1961 के प्रावधानों की दृष्टी से टीडीएस/कर कटौती की दरें निवासी और अनिवासी शेयरधारकों तथा विभिन्न संस्थागत शेयरधारकों के लिए अलग-अलग होती है.
4. जिन मामलों में शेयरधारक फॉर्म 15जी (कंपनी या फर्म के अलावा किसी भी व्यक्ति के लिए लागू) फॉर्म 15एच (60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति के लिए लागू) प्रदान करता है, बशर्ते पात्रता की शर्ते पूरी की जाती है, तो स्त्रोत पर कोई कर कटौती नहीं की जाएगी. कृपया फॉर्म 15जी/15एच/कर रियायत प्रमाणपत्र पैन की प्रति के https://einwardsbi.alankit.com पर जमा करें.
5. यदि आयकर कानून 1961 के प्रावधानों के अनुसार, आवासीय स्थिति में कोई परिवर्तन होता है, तो कृपया sbi.div@alankit.com पर ईमेल द्वारा या हमारे आरटीए को नीचे दिए गए पते पर 31.05.2022 से पहले पत्र द्वारा सूचित करें.
6. कृपया उपयुक्त टीडीएस की कटौती/कर कटौती दर का निर्धारण और कटौती करने के लिए 31 मई 2022 तक या उससे पहले ऊपर वर्णित दस्तावेज जमा करें/निवासी दर्जे की पुष्टि करें. 31 मई 2022 के बाद कर निर्धारण/कटौती पर किए जाने वाले किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा. फिर भी, यदि उक्त लाभांश पर कर की कटौती ऊपर वर्णित विवरणों/आपसे दस्तावेजों की प्राप्ति नहीं होने पर उच्चतर दर पर की जाती है तो भी आपके पास आय की वापसी दायर करने और उपयुक्त धन वापसी, यदि पात्र हो, का दावा करने का विकल्प होगा.
7. इस अवसर पर हमारा आपसे निवेदन है कि आप केवाईसी डाटा, ईमेल आईडी, पता, मोबाइल नंबर और बैंक खाता विवरण अपने डीपी (यदि शेयर्स डीमैट स्वरुप में धारण किए गए है)/आरटीए (यदि शेयर्स कागजी स्वरुप में धारण किए गए है) के साथ अद्यतन करें, ताकि पत्राचार करने और निर्बाध रूप से अंतरण करने में आसानी हो सके.
8 कागजी शेयरधारकों से शेयर्स को डीमैट स्वरुप में रूपांतरित करने के लिए अपने डीपी के पास अपना रु. 1 अंकित मूल्य का एसबीआई शेयर प्रमाणपत्र जमा कराते हुए तुरंत शेयर्स को डीमैट करने का निवेदन किया जाता है. यदि आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप डिपॉजिटरी पाटीसिपेंट (डीपी) के पास आवेदन और आधिकारिक रूप से वैध केवाईसी (नो योर कस्टमर) दस्तावेज यानी (ए) पैन (बी) आधार कार्ड (सी) पासपोर्ट (डी) मतदाता पहचान पत्र (ई) ड्राइविंग लाइसेंस (एफ) कैसल्ड चेक इत्यादि जमा करके डीमैट खाता खोल सकते हैं.
9. उपरोक्त लाभांश भुगतान के संबंध में किसी भी पूछताछ के लिए कृपया sbi.div@alankit.com पर मेल करें या हमारे आरटीए को निम्नलिखित पते पर पत्र भेजें:
युनिटः भारतीय स्टेट बैंक, मे. एलेंकिट (अलंकित) असाइनमेंट्स लिमिटेड,
205-208, अनारकली कॉम्प्लेक्स, झंडेवाला एक्सटेंशन, नई दिल्ली - 110055.
टेलीफोन: 7290071335
किसी भी आगे की कारवाई के लिए, आप investor.complaints@sbi.co.in पर ईमेल भी भेज सकते हैं.
आपके सहयोग और समर्थन के लिए धन्यवाद.

भारतीय स्टेट बैंक हेतु
शाम के.
स्थान : मुंबई सहायक महाप्रबंधक
दिनांक : 21.05.2022 (अनुपालन एवं कंपनी सचिव)

वित्त क्षेत्र के प्रमुखों के लिए नया निकाय

निकुंज ओहरी
नई दिल्ली, 20 मई

केंद्र सरकार के कदम

- 2016 - स्वतंत्र सिफारिश करने वाले निकाय के रूप में बीबीबी का गठन
- 2019 - बीबीबी का कार्य क्षेत्र बढ़ाकर सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों के एमडी, सीएमडी और बोर्ड के अन्य पदों पर नियुक्ति तक किया गया
- अक्टूबर 2021 - दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक फैसले में बीबीबी की सिफारिशों को दरकिनार कर दिया था, जो बीमा कंपनियों के जनरल मैनेजर और निदेशकों की नियुक्ति के लिए थी
- अप्रैल 2022 - बीबीबी के चेयरमैन और 3 अंशकालिक सदस्यों का कार्यकाल खत्म

केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी), सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों (पीएसआईसी) और वित्तीय संस्थानों के प्रमुखों की नियुक्ति के लिए सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड (पीईएसबी) जैसे निकाय के गठन का प्रस्ताव किया है।

वित्तीय सेवा संस्थान बोर्ड (एफएसआईबी) को पीएसबी, सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों और सभी सरकारी वित्तीय संस्थानों के लिए नियुक्तियों की सिफारिश करने का अधिकार होगा। सरकार वित्तीय क्षेत्र की नियुक्तियों से दूरी बनाए रखने को इच्छुक है। एक अधिकारी ने कहा, 'एक प्रस्ताव लाया गया है, जिसके तहत एक साझा निकाय होगा और वह सभी सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों में नियुक्ति संबंधी सिफारिश करेगा।' एक अन्य अधिकारी ने कहा कि बैंक बोर्ड ब्यूरो (बीबीबी) का विलय नई इकाई में किया जा सकता है, जिसमें नए सदस्य हो सकते हैं।

पहले अधिकारी ने कहा कि इस तरह के संस्थान के चार्टर में यह शामिल होगा कि यह निकाय बैंकों, बीमा कंपनियों और वित्तीय संस्थानो में नियुक्ति की सिफारिशें दे सकता है।

सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों के जनरल मैनेजरों और निदेशकों के पद पर नियुक्ति के लिए बीबीबी के सुझावों को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दरकिनार किए जाने के बाद यह पुनर्गठन की कवायद की गई है। बीबीबी के चेयरमैन भानु प्रताप शर्मा और तीन अंशकालिक सदस्यों वेदिका भंडारकर, पांजा प्रदीप कुमार और प्रदीप पन्नालाल शाह का कार्यकाल 10 अप्रैल, 2022 को खत्म हो गया था। सरकार ने अब तक न तो किसी नए चेयरमैन या सदस्य की नियुक्ति की है, न पहले के पदाधिकारियों के कार्यकाल बढ़ाए हैं।

बैंक बोर्ड ब्यूरो का गठन 2016 में सिफारिश करने वाले स्वायत्त निकाय के रूप में किया गया था, जिसे सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंक्स (प्रबंधन व विविध प्रावधान) योजना 1980 के तहत अधिसूचित किया था। बीबीबी के गठन और कामकाज के लिए यह एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है। इसके कामकाज में बैंकों के बोर्ड आफ डायरेक्टरो के चयन और नियुक्ति की सिफारिश करना शामिल है। साथ ही यह केंद्र सरकार को नियुक्ति, कन्फर्मेशन या कार्यकाल में विस्तार और निदेशकों की सेवाएं रद्द करने सहित अन्य सलाह देना था। यह भी कहा गया था कि सरकारी बैंकों को कारोबार की रणनीति विकसित करने और पूंजी जुटाने की योजना बनाने में मदद की जाए। 2019 में बीबीबी के कामकाज करने का दायरा बढ़ा दिया गया और इसमें सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों में नियुक्ति को भी शामिल कर लिया गया। बहरहाल बीबीबी द्वारा इस तरह की नियुक्तियों की कानूनी वैधता को न्यायालय में चुनौती दी गई।

उपरोक्त उल्लिखित अधिकारी ने कहा कि सरकार भविष्य में किसी विषम स्थिति से बचने के लिए नई इकाई का कामकाज साफ साफ वर्णित करेगी। यह निकाय पीईएसबी की जगह ले सकता है, जिसका गठन केंद्र सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (पीएसयू) और सरकार द्वारा उल्लिखित किसी अन्य स्तर पर नियुक्तियों को लेकर सलाह देने के लिए किया गया था।

पीईएसबी में एक चेयरमैन और 3 सदस्य होंगे। सरकार ने पीईएसबी के चेयरपर्सन के रूप में निजी क्षेत्र के पहले विशेषज्ञ के रूप में मल्लिका श्रीनिवासन को चुना है।

आईएमएफ ने सुधारा गणित

इंदिवजल धस्माना
नई दिल्ली, 20 मई

- **अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा कि वित्त वर्ष 27 तक भारत बनेगा पांच लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था**

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने अपनी गणना की एक त्रुटि में सुधार करते हुए अब यह अनुमान जताया है कि भारत वर्ष 2026-27 तक पांच लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। यह वही बात है, जो वित्त मंत्रालय पहले से कहता आ रहा है। पिछले महीने आईएमएफ द्वारा दिए गए आंकड़ों में बताया गया था कि यह लक्ष्य वर्ष 2028-29 तक ही हासिल किया जा सकता है, जो मंत्रालय के नवीनतम अनुमानों के दो साल बाद और सरकार द्वारा निर्धारित मूल लक्ष्य से चार साल के विलंब वाली अवधि थी।

आईएमएफ में भारत, नेपाल और भूटान के वरिष्ठ रेजिडेंट प्रतिनिधि लुइस ई ब्रेउर ने ईमेल के जवाब में बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया कि आईएमएफ के कर्मचारियों ने डेटा इनपुट की एक त्रुटि का पता लगाया है, जिसकी वजह से भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की डॉलर में गणना में त्रुटि हुई थी, जिसे ठीक किया गया था। उन्होंने कहा कि रुपये में वास्तविक और नॉमिनल जीडीपी के आंकड़े प्रभावित नहीं होते हैं। ब्रेउर ने कहा कि अधिक व्यापक रूप से कहें, तो भारतीय अर्थव्यवस्था महामारी से अच्छे ढंग से उबर रही है। वास्तविक जीडीपी मार्च 2022 के अंत तक के महामारी से पहले के अपने स्तर से सुधरकर इससे अधिक होने का अनुमान है। यह सुधार जारी रहने की उम्मीद है, हालांकि इसे बाहरी कारकों सहित नकारात्मक जोखिमों का सामना करना पड़ रहा है।

दिलचस्प बात यह है कि मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने इस महीने की शुरुआत में एक समारोह में आईएमएफ के अनुमानों से असहमति जताई थी।

कर्नाटक के लौह अयस्क निर्यात को मिली अनुमति

भाविनी मिश्र और ईशिता आयान दत्त
नई दिल्ली/कोलकाता, 20 मई

उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक के बेल्लारी, चित्रदुर्ग और तुमकुर जिलों की खदानों से लौह अयस्क के निर्यात पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है। न्यायालय ने खननकर्ताओं को सीधी बिक्री के माध्यम से अयस्क की बिक्री की अनुमति भी दे दी है।

मुख्य न्यायाधीश एनवी रमण, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति हिमा कोहली के पीठ ने खनन फर्मों के आवेदनों पर आदेश देते हुए उनसे कहा है कि लौह अयस्क के निर्यात को लेकर भारत सरकार के नियमों का पालन किया जाना चाहिए।

पीठ ने कहा, 'ऐसा बताया गया है कि लगातार ई-नीलामियों में खराब प्रतिक्रिया मिल रही है। कुल मिलाकर बदलाव को देखते हुए अयस्क की बिक्री पर प्रतिबंध और कीमत पर प्रतिबंध हटाए जाने की जरूरत है। हम आवेदकों को पहले से निकाले जा चुके लौह अयस्क के स्टॉक की बिक्री की अनुमति देते हैं, जो कर्नाटक के 3 जिलों में है। अपीलकर्ताओं को सीधे संपर्क कर लौह अयस्क आवंटन करने की अनुमति दी जाती है, इसमें ई नीलामी की जरूरत नहीं है। कर्नाटक में उत्पादन होने वाले लौह अयस्क का निर्यात किया जा सकता है, लेकिन यह भारत सरकार की नीतियों के मुताबिक होगा।'

शीर्ष न्यायालय ने 2011 में कर्नाटक में लौह अयस्क खनन पर प्रतिबंध लगा दिया था। न्यायालय ने पर्यावरण को होने वाले नुकसान का हवाला देते हुए और भविष्य के लिए खनिज संसाधनों को बचाने के मकसद से यह प्रतिबंध लगाया था। साथ ही न्यायालय ने निर्यात पर भी प्रतिबंध लगा दिया था।

शुक्रवार के आदेश के बाद निर्यात पर लगी रोक खत्म हो गई है और लौह अयस्क खननकर्ताओं को निकाले गए लोहे की सीधी बिक्री की अनुमति मिल गई है।

दिल्ली इकनॉमिक्स कॉन्क्लेव का नए नाम से होगा आयोजन

अरूप रॉयचौधरी
नई दिल्ली, 20 मई

- **कौटिल्य इकनॉमिक्स कॉन्क्लेव के नाम से संभवतः जून या जुलाई में आयोजित किया जाएगा कार्यक्रम**
- **वर्ष 2015 में बंद किए जाने के बाद फिर से हो रही कार्यक्रम की वापसी**

नीतिगत चर्चाओं के लिए वित्त मंत्रालय का प्रमुख वार्षिक कार्यकम - दिल्ली इकनॉमिक्स कॉन्क्लेव वर्ष 2015 में बंद किए जाने के बाद फिर से वापसी के लिए तैयार है। बिजनेस स्टैंडर्ड को जानकारी मिली है कि कौटिल्य इकनॉमिक्स कॉन्क्लेव के नाम से यह संभवतः जून या जुलाई में आयोजित किया जाएगा। दिल्ली इकनॉमिक्स कॉन्क्लेव नवंबर या दिसंबर में आयोजित किया जाता था।

इसकी नवीनतम पुनरावृत्ति के लिए वित्त मंत्रालय के आर्थिक अनुभाग ने थिंक-टैंक - आर्थिक विकास संस्थान (आईईजी) के साथ करार किया है।

हालांकि इस संबंध में अब भी अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिसमें सम्मेलन का विषय भी शामिल है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि सभा को संबोधित करने वालों में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वित्त सचिव टीवी सोमनाथन, आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ, मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन शामिल हो सकते हैं।

अन्य विभागों के मंत्री और अफसरशाह तथा नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी और पंद्रहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह सहित सलाहकार भी इस कार्यक्रम को संबोधित कर सकते हैं।

इसके अलावा भारत और विश्व के स्वतंत्र अर्थशास्त्री तथा विभिन्न थिंकटैंक के प्रमुख भी सम्मेलन में हिस्सा ले सकते हैं और संबोधित कर सकते हैं।

आरबीआई देगा 30,307 करोड़ का अधिशेष

पृष्ठ 1 का शेष

बैंक ऑफ बड़ौदा में मुख्य अर्थशास्त्री मदन सबनवीस ने कहा, 'इस साल सरकार ने आरबीआई, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) और अन्य सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों से लाभांश या अधिशेष के रूप में करीब 74,000 करोड़ रुपये हासिल करने का लक्ष्य तय किया है। इसका मतलब है कि पीएसबी और वित्तीय संस्थानों के लाभ का एक बड़ा हिस्सा हस्तांतरित करना होगा ताकि यह आंकड़ा अच्छा नजर आए अन्यथा सरकार यह लक्ष्य हासिल करने से चूक जाएगी।' सबनवीस ने कहा, 'वित्त वर्ष 2022 में आरबीआई के 3.5 फीसदी की औसत लागत पर रोजाना औसतन 6 से 7 लाख करोड़ रुपये की रिवर्स रीपो नीलामियों का मतलब है कि 21,000 से 24,500 करोड़ रुपये की लागत आई है। यह धनराशि सरकार को मिलती और उसे प्राप्त होने वाला अधिशेष अधिक होता।' हाल में सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) को शेयर बाजार में सूचीबद्ध कर 20,500 करोड़ रुपये से अधिक रकम जुटाई है।

इक्रा की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर ने कहा, 'आरबीआई की तरफ से सरकार को हस्तांतरित किए जाने वाले अधिशेष की राशि बजट अनुमान से थोड़ी कम नजर आ रही है। हालांकि कर प्राप्तियां बजट स्तर से काफी अधिक रहने के आसार हैं, जो कम अधिशेष हस्तांतरण के असर की भरपाई करेंगी।' आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल ने बैठक में मौजूदा आर्थिक हालात, वैश्विक एवं घरेलू चुनौतियों और मौजूदा भूराजनीतिक घटनाक्रमों के असर की समीक्षा की।

3 महीने में कम से कम 10 प्रतिशत बढ़ा मासिक बजट

- **लोकलसर्किल के सर्वे में 92 प्रतिशत लोगों ने कहा है कि 3 महीने के दौरान उनके परिवार के मासिक खर्च में हुआ इजाफा**

लोकलसर्किल की ओर से कराए गए एक सर्वे में शामिल 92 प्रतिशत लोगों ने कहा है कि पिछले 3 महीने के दौरान उनके परिवार का मासिक खर्च बढ़ा है। यह बढ़ोतरी पेट्रोल, डीजल, खाद्य तेल, परिवार के जरूरी सामान व अन्य संबंधित उत्पादों व सेवाओं के महंगा होने की वजह से हुआ है।

कम से कम 70 प्रतिशत लोगों का कहना है कि उनके मासिक बजट में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई हैष वहीं 55 प्रतिशत को उम्मीद है कि अगले 3 महीने में कीमतों में 10 प्रतिशत और बढ़ोतरी होगी। लोकल सर्किल द्वारा कराए गए सर्वे में 323 जिलों के 12,000 से ज्यादा परिवारों के 23,500 से ज्यादा लोगों ने प्रतिक्रिया दी है। लोकल सर्किल कम्युनिटी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जो नागरिकों को लघु उद्योगों में सक्षम बनाता है और नीतिगत मसलों को उठाकर उस दिशा में हस्तक्षेप पर जोर देता है। लोकल सर्किल का कहना है कि पेट्रोल व डीजल की कीमत में कमी किए जाने से परिवारों के व्यय पर बड़ा असर पड़ेगा। केंद्र व राज्य सरकारों को निश्चित रूप से मूल्यांकन करना चाहिए कि वे कम से कम 10 रुपये लीटर की राहत किस तरह से दे सकती हैं। अगर केंद्रीय उत्पाद शुल्क और राज्य के मूल्यवर्धित कर में बढ़ोतरी की जाती है तो ईंधन की बढ़ी कीमत का परिवारों के बजट पर पड़ने वाले नकारात्मक असर को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। *बीएस*

एफडीआई आवक 2021-22 में रही शीर्ष स्तर पर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि भारत ने वित्त वर्ष 2021-22 में 83.57 अरब अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) हासिल किया जो अब तक किसी भी वित्त वर्ष में सबसे अधिक है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारत ने वित्त वर्ष 2021-22 में 83.57 अरब अमेरिकी डॉलर की अब तक सर्वाधिक सालाना एफडीआई आवक दर्ज की। इससे पहले वित्त वर्ष 2020-21 में एफडीआई आवक 81.97 अरब अमेरिकी डॉलर थी। मंत्रालय ने कहा कि भारत विनिर्माण क्षेत्र में विदेशी निवेश के लिए एक पसंदीदा देश के रूप में तेजी से उभर रहा है। विनिर्माण क्षेत्रों में एफडीआई इक्विटी आवक 2020-21 (12.09 अरब डॉलर) की तुलना में 2021-22 में (21.34 अरब डॉलर) 76 प्रतिशत बढ़ी। प्रमुख निवेशक देशों के मामले में सिंगापुर 27 प्रतिशत के साथ शीर्ष पर है। इसके बाद अमेरिका (18 प्रतिशत) और मॉरीशस (16 प्रतिशत) का स्थान है। भाषा

बीएस सूडोकू 4362

				5				
						8		
			9			6		2
		5	2	3				
	1				7	5		
7		2		8				4
8					5			3
2	9		3				4	
5							1	

परिणाम संख्या 4361

1	5	6	2	9	4	7	3	8
3	2	7	8	1	6	4	5	9
8	4	9	7	5	3	6	1	2
9	7	2	1	3	8	5	6	4
4	1	8	5	6	9	3	2	7
5	6	3	4	2	7	8	9	1
7	9	1	3	8	5	2	4	6
2	8	5	6	4	1	9	7	3
6	3	4	9	7	2	1	8	5

कैसे खेलें?
हर, रो, कॉलम और 3 के बाई 3 के बॉक्स में एक से लेकर नौ तक की संख्या भरें।

मध्यम ★★★☆☆

क्षेत्रीय मंडियों के भाव

महाराष्ट्र | राजस्थान | मध्य प्रदेश

बंद भाव रुपये प्रति क्विंटल

मुंबई

अनाज-दाल : गेहूंः लोकवन 2600/2700, शरबती 3000/3250, थाना मिल 2375/2400, चावलः परमल वंड 2900/3000,कोलम (कर्नाटक) 4900/5000, कोलम (नागपुर) 4900/5100, मंसूरी 2700/2800, दाल : राजमां चित्रा 12700/13200, राजमां ब्राजील 12200/12800, राजमा इथियोपिया 12000/12200, मसूर 6940/6950, उड़द एफएक्यू 6775/6800, उड़द एसक्यू 7300/7325, अरहर लेमन 6225/6250

गुड़-चीनी : चीनीः एस ग्रेड 3382/3472, एम ग्रेड 3500/3632,गुड़ (भेली): सांगली 4600/5200, नीरा बारामती 3900/4000

तेल-तिल्हन : खाद्य तेलः आरबीडी 15500, मूंगफली तेल 16250, सोया रिफाइंड 15600, सोया रिफाइंड (टिन)2600/2700

किराना : जीराः (20 किलो) मीडियम 4300/4400, जीरा बेस्ट 4400/4500, अजवायन जामनगर 17500/21500, धनियाः ईगल 11100/11500, ग्रीन 11900/12400, लालमिर्च गुंटूर 19500/21500, लालमिर्च एमपी 18000/19500, चाय (किलो): असम डस्ट 290/330, असम मामरी 300/350, साउथ 200/230

सर्राफा (जीएसटी अतिरिक्त) : चांदी (किलो):हाजिर 62000, डिलीवरी 62100, कच्ची 60000, सोना (प्रति दस ग्राम): बार 51250, स्टैण्डर्ड 51000, (23 कैरेट) ×, आभूषण (22 कैरेट) 47300

अलौह-धातु : (किलो): कॉपर सी स्क्रैप 774, कॉपर एच स्क्रैप 764, कॉपर आरमेचर 753, कॉपर शीट कटिंग ×, कॉपर यूटेंशियल स्क्रैप 700, ब्रास शीट कटिंग 571, ब्रास यूटेनसिल स्क्रैप 520, एल्यू. यूटेनसिल स्क्रैप 185, गन मैटल स्क्रैप 565, ब्रास हनी 500, कॉपर बिलेट्स ×, एल्यू. इंगट 241, जिंक इंगट 329, लेड इंगट 185, टिन इंगट 3000, निकिल कैथड 2213, कॉपर सीसी रॉड 792

कॉटन यार्न : (कि लो): कार्डेड वार्पः (10/1) 120/130, (20/1) 210/220, (40/1) 370/385, (60/1) 405/415

देशी घी : (प्रति लीटर): अमूल 470, विजया 475, पारस प्री. ×, कृष्णा 424, गोकुल 540, परम प्री. 445, मधु सुधन 445

सीमेंट : (50 किलो/53 ग्रेड): अल्ट्राटैक 410, एसीसी 410, ग्रासिम ×, वासव दत्ता 400, अम्बुजा 410

रसायन : (एफओआर मुंम्बई) टैक्स अतिरिक्तः कॉस्टिक सोडा फ्लैक (50 किलो) 3250/3275, सोडा एश (50 किलो) 2500/2525, टिटेनियम डाइऑक्साइड (किलो): टीटीके 180/185, चीन 170/175

जयपुर

दाल (जीएसटी अतिरिक्त): मूंग मोगर 8000/8100, मोटा 8500/8600, उड़द मोगर 8500/8700, मोटा 9000/9200, चौला मोगर ×, मोठ मोगर 7900/8000, मूंग दाल छिलका देशी 8500/8600, मलका 8500/8600, अरहर 8400/9000, मटर दाल 7000/7500, चना दाल मीडियम 5800/5900, बोल्ड 5900/6000, दलहनः उड़द साबुत देशी 6700/6900, मटर सफेद 6600/6800, मोठ साबुत 6600/6800, काबली चना 7500/8500, चना (डिली.) 4950/5000, मूंग 6500/6600, राजमा शर्मिली 10000/10600, राजमां चित्रा 13000/14000, किरानाः हल्दी निजामाबाद 8500/9000, सांगली 9500/10500, हल्दी राजापुरी 13000/16000, लालमिर्च 19500/27000, कालीमिर्च (किलो) 550/650, धनिया 13100/14500, जीरा 23200/27000, अजवायन 13000/24500, सौंफ 14000/22000,

इंदौर

जीएसटी अतिरिक्तः किराना (किलो): सुपारी 470/520, हल्दीः सांगली 102/108, निजामाबाद 95/102, कालीमिर्च 540/590, जीराः ऊंझा चालू 21800/21900, मीडियम 22000/22100, बेस्ट 22400/22500, खसखस 1200/1650, बड़ी इलायची 710/750, इलायची हरी 1100/1600, लौंग 700/730, दालचीनी 280/290, जायफल 670/690, जावित्री कोचीन 1710/1760, सिंगापुर 1850/1875, अजवायन मीडियम 140/160, धनिया खड़ा मीडियम 113/124, मेथीदाना 62/65, मेवेः काजू (240 नं.) 780, (320 नं.)680/700, (300 नं.) 640, एसडब्ल्यू 590, काजू-टुकड़ी 470, उड़ीसा (320 नं.) 690/710, (400 नं.) 660, (240 नं.) 790/815, जेएच 700, बादामगिरीः कारमल 680, कैलि. 685/690, लम्बी सिनोरा 790, *एनएनएस*